भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1429
02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग का आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन

1429. श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इसके आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन का समर्थन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) इस्पात विनिर्माण क्षेत्र में पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी नीतियां हैं;

(ग) छोटे और मध्यम आकार के इस्पात उत्पादकों को कच्चा माल प्राप्त करने और अपने उद्यमों के परिचालन के लिए वित्त का प्रबंध करने में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस्पात उद्योग में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) इस्पात उद्योग के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकियों के उन्नयन संबंधी निर्णय अलगअलग कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिये जाते हैं। इस्पात कंपनियां अपने आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों में वैश्विक रूप से सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकियों(बीएटी) को अपना रही हैं।

(ख) इस्पात विनिर्माण क्षेत्र में पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मौजूद नीतियां निम्नानुसार हैं:

- इस्पात मंत्रालय की आरएंडडी योजना यथा "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन" अपने हितधारकों को अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय संधारणीयता तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन तथा इस्पात क्षेत्र सहित विभिन्न अंतिम उपयोग क्षेत्रों में उपयोग हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरूआत की इस मिशन के अंतर्गत, एमएनआरई ने इस्पात मंत्रालय के परामर्श से "इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजना का कार्यान्वयन" नामक योजना को भी अधिसूचित किया है।

जारी.....2/-

- इस्पात के 100 प्रतिशत पुनर्चक्रण योग्य होने के कारण यह पर्यावरणीय दृष्टि से सर्वाधिक संपोषणीय सामग्रियों में से एक है। इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 इस्पात निर्माण में कोयले की खपत को कम करने तथा उत्सर्जन में कमी लाने के लिए स्वदेशी रूप से सृजित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है।
- मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, सितंबर, 2021 में इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है तथा जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है।
- नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना, ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करती है।

(ग) सरकार ने खनिजों की आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए खनन एवं खनिज नीति में सुधार, समाप्त पट्टों वाली खदानों की शीघ्र निलामी तथा प्रचालन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सभी वैध अधिकारों तथा स्वीकृतियों का निर्बाध अंतरण, खनन प्रचालन की शुरूआत तथा प्रेषण को प्रोत्साहित करना, खनन पट्टों का हस्तांतरण, कैप्टिव खदानों को उत्पादित खनिजों के 50% तक की बिक्री करने की अनुमति प्रदान करना, गवेषणात्मक क्रियाकलापों में वृद्धि करना आदि शामिल हैं। इस्पात उद्योग के नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, लघु एवं मध्यम स्तरीय उत्पादकों हेतु उनके प्रचालन के लिए वित्तपोषण की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(घ) भारत में लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का कार्य मुख्यतया लौह एवं इस्पात कंपनियों, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमिक संस्थानों आदि द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाता है। इस्पात मंत्रालय "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन" नामक योजना के अंतर्गत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए इस्पात उद्योग, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं तथा अकादमिक जगत को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपशिष्टों का उपयोग, दक्षता एवं उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा खपत तथा उत्सर्जनों में कमी, इस्पात उत्पादों आदि की गुणवत्ता में सुधार जैसी इस्पात क्षेत्र के समक्ष आ रही सामान्य समस्याओं के समाधान करने के लिए अनुसंधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया गया है।

****